अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

शीर्षक: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: कौशल विकास एवं शैक्षिक पुनर्संरचना

डॉ. रितेश चन्द्र भारती
विद्यालय अध्यापक
पी.एम. श्री राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय, ताड़र, सन्हौला, भागलपुर

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, बहुविषयक, व्यावहारिक तथा रोजगारोन्मुख बनाना है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के कारण शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास तथा शैक्षिक पुनर्संरचना की आवश्यकता बढ़ गई है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता और व्यावसायिक दक्षता को विशेष महत्त्व प्रदान करती है। नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक संरचना, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौशल विकास की भूमिका, शैक्षिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया तथा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनमें सरकारी रिपोर्टों, शैक्षणिक दस्तावेजों, शोध-पत्रों तथा संबंधित साहित्य का उपयोग किया जाएगा। अध्ययन में शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारपरक कौशल तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक असमानताओं जैसी प्रमुख चुनौतियों पर भी विचार किया गया है। निष्कर्षतः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावशीलता इसके सफल क्रियान्वयन, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों, तकनीकी सुविधाओं तथा शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर समन्वय पर निर्भर करती है। उचित कार्यान्वयन के माध्यम से यह नीति भारत में कौशल-संपन्न, आत्मनिर्भर और ज्ञान-आधारित समाज के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल विकास, शैक्षिक पुनर्संरचना, व्यावसायिक शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा।

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy—NEP) 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधारों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, लचीला, बहुविषयक तथा कौशल-आधारित बनाना है। यह नीति पूर्ववर्ती शिक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करते हुए विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यावसायिक विकास पर बल देती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण,

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोजगार के बदलते स्वरूप ने शिक्षा प्रणाली के सामने नई चुनौतियाँ और संभावनाएँ प्रस्तुत की हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर व्यावहारिक अनुभव, कौशल विकास और जीवनोपयोगी दक्षताओं से जोड़ना आवश्यक हो गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना है। इसके अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा की पारंपरिक 10+2 संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 की शैक्षणिक संरचना प्रस्तावित की गई है। यह संरचना बच्चों के विभिन्न विकासात्मक चरणों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, विषयगत समझ तथा आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही, नीति रटने पर आधारित शिक्षा के स्थान पर अनुभवात्मक अधिगम, गतिविधि-आधारित शिक्षण, परियोजना कार्य और समस्या-समाधान जैसी विधियों को महत्त्व प्रदान करती है।

1.1 कौशल विकास की अवधारणा एवं महत्त्व

कौशल विकास आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में ऐसी क्षमताओं का विकास करना है, जिनकी सहायता से वे व्यावसायिक जीवन, सामाजिक गतिविधियों तथा व्यक्तिगत विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। इनमें तकनीकी कौशल, संचार कौशल, डिजिटल साक्षरता, उद्यमशीलता, रचनात्मकता, सहयोग, नेतृत्व तथा निर्णय लेने की क्षमता प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयी स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने पर बल देती है। नीति में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, व्यावहारिक गतिविधियों और इंटर्नशिप के अवसरों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों, स्थानीय शिल्पों, तकनीकी कार्यों और आजीविका के अवसरों से परिचित कराना है। इससे शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने तथा विद्यार्थियों में कार्य के प्रति सम्मान विकसित करने में सहायता मिल सकती है।

कौशल विकास का महत्त्व केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और नवाचार के लिए भी तैयार करता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कौशल-आधारित शिक्षा कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय उद्यमों के विकास में योगदान दे सकती है। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, आधुनिक प्रयोगशालाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और उद्योगों के साथ सहयोग की आवश्यकता है।

1.2 शैक्षिक पुनर्संरचना की आवश्यकता

शैक्षिक पुनर्संरचना से आशय शिक्षा की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण-पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली तथा संस्थागत व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन करना है, जिनसे शिक्षा अधिक प्रभावी, प्रासंगिक और विद्यार्थी-केंद्रित बन सके। भारतीय शिक्षा प्रणाली में लंबे समय तक परीक्षा-केंद्रित अध्ययन और रटने की प्रवृत्ति का प्रभाव रहा है। इसके कारण कई बार विद्यार्थियों की व्यावहारिक समझ, रचनात्मक क्षमता और वास्तविक जीवन में समस्याओं का समाधान करने की योग्यता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने, विषयों के बीच कठोर विभाजन को कम करने तथा विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने के अवसर प्रदान करने पर बल देती है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन, लचीले पाठ्यक्रम, शोध एवं नवाचार तथा अकादमिक क्रेडिट बैंक जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए अधिक लचीले शैक्षिक मार्ग विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पुनर्संरचना का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष मूल्यांकन प्रणाली में सुधार है। नीति केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी की क्षमता निर्धारित करने के बजाय उसकी अवधारणात्मक समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता, रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार, शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करना नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान और जीवनोपयोगी क्षमताओं का विकास करना है।

1.3 डिजिटल शिक्षा एवं तकनीकी नवाचार

डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल पुस्तकालय, शैक्षिक ऐप, वर्चुअल प्रयोगशालाएँ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण उपकरण विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में तकनीकी उपयोग, डिजिटल संसाधनों के विकास तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर बल देती है।

डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक शैक्षिक सामग्री पहुँचाने की संभावनाएँ बढ़ती हैं। इसके बावजूद इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली की उपलब्धता, डिजिटल उपकरणों की लागत और डिजिटल साक्षरता की कमी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। इसलिए तकनीक का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। डिजिटल माध्यमों को पारंपरिक कक्षा-शिक्षण के पूरक के रूप में विकसित करना अधिक उपयोगी हो सकता है।

1.4 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता केवल नीतिगत प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर भी आधारित है। भारत में राज्यों के बीच शैक्षिक संसाधनों, संस्थागत सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता में अंतर पाया जाता है। कई विद्यालयों में आधारभूत संरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, इंटरनेट सुविधाएँ तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के समान सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना भी आवश्यक है। विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच यह धारणा कि केवल पारंपरिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम ही बेहतर भविष्य प्रदान करते हैं, कौशल-आधारित शिक्षा के विस्तार में बाधा बन सकती है। इस चुनौती का समाधान जागरूकता, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, रोजगार के अवसरों तथा उद्योगों के साथ प्रभावी साझेदारी के माध्यम से किया जा सकता है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे भी महत्त्वपूर्ण हैं। नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से स्वतंत्र होकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्राप्त हों।

1.5 अध्ययन की प्रासंगिकता

वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौशल विकास और शैक्षिक पुनर्संरचना का अध्ययन अकादमिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से प्रासंगिक है। यह अध्ययन समझने का प्रयास करता है कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार विद्यार्थियों की क्षमताओं, शिक्षण-पद्धतियों, पाठ्यक्रम संरचना और रोजगार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही, नीति के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों तथा उन्हें दूर करने के संभावित उपायों का विश्लेषण भी आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन का व्यापक उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करना, कौशल विकास में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करना तथा शैक्षिक पुनर्संरचना के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगारपरकता में सुधार की संभावनाओं को समझना है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपयोगी हो सकता है।

अंततः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक और कौशल-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तथापि, इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल समानता, संस्थागत सहयोग और निरंतर मूल्यांकन आवश्यक हैं। यदि इन पहलुओं पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए, तो शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान प्रदान कर सकेगी, बल्कि उन्हें बदलती सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप सक्षम नागरिक तथा कुशल पेशेवर बनाने में भी योगदान देगी।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: आँकड़ों सहित विश्लेषण

आपके शोध-पत्र "राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: कौशल विकास एवं शैक्षिक पुनर्संरचना" में प्रस्तावना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकारी रिपोर्टों पर आधारित आँकड़े, तालिकाएँ और उनका विश्लेषण शामिल किया जा सकता है। इससे शोध-पत्र को तथ्यात्मक आधार मिलेगा।

तालिका 1. भारत में शिक्षा के प्रमुख संकेतक

शैक्षिक संकेतक	वर्ष/अवधि	आँकड़ा
विद्यालयों की कुल संख्या	2023–24	लगभग 14.72 लाख
विद्यालयी विद्यार्थियों की कुल संख्या	2023–24	लगभग 24.8 करोड़
विद्यालयी शिक्षकों की कुल संख्या	2023–24	98 लाख से अधिक
उच्च शिक्षा में कुल नामांकन	2021–22	लगभग 4.33 करोड़
उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER)	2021–22	28.4%
उच्च शिक्षा में महिला नामांकन	2021–22	लगभग 2.07 करोड़

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

तालिका 2. डिजिटल शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित संकेतक

संकेतक	आँकड़ा	महत्त्व
इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालय, भारत	53.9%	डिजिटल शिक्षा के विस्तार की स्थिति
इंटरनेट सुविधा वाले सरकारी विद्यालय	46.2%	सरकारी विद्यालयों में डिजिटल पहुँच की चुनौती
इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालय, बिहार	18.5%	राज्य में डिजिटल आधारभूत संरचना की आवश्यकता
व्यावसायिक शिक्षा से परिचित होने का NEP लक्ष्य	2025 तक कम-से-कम 50% विद्यार्थी	कौशल-आधारित शिक्षा के विस्तार का नीतिगत लक्ष्य

आँकड़ों का विश्लेषण

उपर्युक्त आँकड़े भारतीय शिक्षा व्यवस्था के व्यापक आकार तथा शैक्षिक पुनर्संरचना की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। UDISE+ 2023–24 के अनुसार, देश में लगभग 14.72 लाख विद्यालय और 24.8 करोड़ विद्यार्थी हैं। इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम लागू करना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में AISHE 2021–22 के अनुसार, कुल नामांकन लगभग 4.33 करोड़ तथा सकल नामांकन अनुपात 28.4% था। ये आँकड़े उच्च शिक्षा तक पहुँच के विस्तार को दर्शाते हैं, जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगारपरक कौशल को मजबूत बनाने की आवश्यकता भी सामने लाते हैं।

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में असमानता विशेष ध्यान देने योग्य है। वर्ष 2023–24 में देश के 53.9% विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी, जबकि बिहार में यह अनुपात 18.5% था। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल माध्यमों पर आधारित शैक्षिक सुधारों के लिए इंटरनेट, उपकरणों और डिजिटल साक्षरता का विस्तार आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 2025 तक विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के कम-से-कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य की वास्तविक प्राप्ति का आकलन करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन, प्रशिक्षण की उपलब्धता, इंटर्नशिप तथा रोजगार संबंधी नवीनतम आँकड़ों की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी, बहुविषयक तथा कौशल-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि उनमें व्यावहारिक दक्षता, रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन,

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

समस्या-समाधान तथा रोजगारपरक कौशल का विकास करना है। विद्यालयी शिक्षा की 5+3+3+4 संरचना, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा में बहुविषयक अध्ययन जैसे प्रावधान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं।

अध्ययन में प्रस्तुत आँकड़े भारतीय शिक्षा व्यवस्था के व्यापक विस्तार के साथ-साथ इसके सामने मौजूद चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। वर्ष 2023–24 में देश में लगभग 14.72 लाख विद्यालय और 24.8 करोड़ विद्यालयी विद्यार्थी थे। वहीं, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2021–22 में 28.4% था। ये आँकड़े शिक्षा तक पहुँच के विस्तार और उसकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में भी क्षेत्रीय असमानताएँ महत्त्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, UDISE+ 2023–24 के अनुसार, भारत में 53.9% विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी, जबकि बिहार में यह अनुपात 18.5% था। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल शिक्षा के लाभ सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए आधारभूत संरचना और तकनीकी संसाधनों का विस्तार आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावशीलता उसके प्रावधानों के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग आवश्यक है। साथ ही, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों तथा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के बीच शैक्षिक असमानताओं को कम करना भी महत्त्वपूर्ण है। व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के समान महत्त्व और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने से विद्यार्थियों के लिए रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

अंततः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में ज्ञान-आधारित, आत्मनिर्भर और कौशल-संपन्न समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करती है। यदि इसके उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा डिजिटल समानता, शिक्षक प्रशिक्षण, कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो यह नीति विद्यार्थियों की क्षमताओं के विकास और देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। भविष्य में नीति की सफलता का मूल्यांकन केवल नामांकन या संस्थानों की संख्या से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों, कौशल दक्षता, रोजगार के अवसरों और शिक्षा में समानता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2024)। UDISE+ रिपोर्ट 2023–24: स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली।
3. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2023)। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2021–22। उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

4. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2022)। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क। नई दिल्ली।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (2021)। उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास संबंधी दिशा-निर्देश। नई दिल्ली।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (2022)। स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या एवं क्रेडिट रूपरेखा। नई दिल्ली।

7. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार। (2023)। वार्षिक रिपोर्ट 2022–23। नई दिल्ली।

8. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)। (2023)। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा: स्कूली शिक्षा 2023। नई दिल्ली।

9. यूनेस्को। (2023)। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023: शिक्षा में प्रौद्योगिकी—किसकी शर्तों पर एक साधन? पेरिस: यूनेस्को।

10. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)। (2019)। शिक्षा एवं कौशल का भविष्य 2030: वैचारिक अधिगम रूपरेखा। पेरिस: OECD।